

<><><><><><><><>

- सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2025 के लिए नामांकन अब 31 जुलाई तक कराये जा सकते हैं।
- द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने प्रशासक सलाहकार परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया है।
- एम वी सिंधु और एम वी कैम्पबेल बे के यात्रा कार्यक्रम में संशोधन।

<><><><><><><><>

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई वैश्विक कंपनियों ने इस संबंध में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सहित सात वैश्विक फर्मों ने आज मुंबई में वेक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईसीटी की स्थापना 400 करोड़ रुपये की फंडिंग के साथ मुंबई में की जाएगी। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले दिनों में आई आई सी टी, आई आई टी और आई आई एम के समान मान्यता प्राप्त करेगा।

इससे पहले, उन्होंने कहा था कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू भी उपस्थित थे।

<><><><><><><><>

पांच से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2025 के लिए नामांकन अब इस वर्ष 31 जुलाई तक कराये जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। सभी नामांकन आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था पुरस्कार के लिए असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को नामांकित कर सकती है। बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

<><><><><><><><>

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के अवसर पर कल केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्यारी की प्रमुख वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई की प्रभारी डॉ. टी. सुजाता ने बताया कि संस्थान के आईपीआर पोर्टफोलियो में 10 स्वीकृत पेटेंट, 9 पशु और पौधे आनुवंशिक जर्मप्लाज्म पंजीकृत, 11 प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण, 6 आईसीएआर प्रमाणित प्रौद्योगिकियां और एक ट्रेडमार्क के साथ काफी सुधार हुआ है। क्यारी के निदेशक डॉ. ई.बी. चाकुरकर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में कुछ आईपी है जिसे तलाशने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। आईपीआर संरक्षण पर जागरूकता जारी रखने की जरूरत है। कार्यक्रम में क्यारी, आईसीएमआर और एन आई ओ टी के वैज्ञानिकों, परियोजना कर्मचारियों और छात्रों सहित कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

<><><><><><><><>

द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने प्रशासक सलाहकार परिषद की बैठक तत्काल बुलाने का आग्रह किया है। उप-राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि 24 जून, 2010 की अंडमान निकोबार प्रशासन अधिसूचना के तहत स्थापित यह एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र है। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई सलाहकार परिषद को द्वीपसमूह से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए हर तीन महीने में बैठक करने का अधिकार है। यह मंच जन प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों के साथ परामर्श की सुविधा प्रदान करके सहयोगात्मक शासन सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद सलाहकार परिषद की कोई बैठक से नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप परिषद के सदस्यों के सुझाव के बिना निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने उप-राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, ताकि द्वीपसमूह के कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक चर्चा हो सके।

